

[2023] 6 एस. सी. आर. 469

ए.

कप्तान मंजीत सिंह विरदी (सेवानिवृत्त)बी.

हुसैन मोहम्मद शताफ और ओआरएस। (2023 की आपराधिक अपील संख्या 1399)

बी.

18 मई, 2023

[अभय एस. ओका और राजेश बिंदल, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-छुट्टी के लिए आवेदन-पीड़ित का शव उसके शयनकक्ष में खून से लथपथ पाया गया था-अनुसंधान के बाद, प्रत्यर्थी संख्या के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। 1 & 2 – निचली अदालत ने अभी तक आरोप तय नहीं किए थे-आरोप पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद, आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया गया था-इसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया और प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. को आरोपमुक्त कर दिया। 1 और 2-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीआप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीचप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीणप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीअप्रत्यर्थीभप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीषप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीषप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीशप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीचप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी-प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीबप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी

[illegible]

प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीभप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीथप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी

प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीफप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीइप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीगप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीफप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीषप्रत्यर्थीणप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीऔप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीषप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीषप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीफप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीइप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीगप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी(प्रत्यर्थीबप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थीओप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी)प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीषप्रत्यर्थीणप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीशप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीथप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी।प्रत्यर्थी1 - प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. 1 और 2 को बिना विवेक के आरोपमुक्त कर दिया गया था-उच्च न्यायालय ने एक जघन्य अपराध के मुकदमे को बाधित करने के लिए इस तरह से अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था जो इसमें निहित नहीं है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

जी.

पकड़ना:1. अभियुक्त के आरोपमुक्त किए जाने के समय किस पर विचार किया जाना चाहिए, इस मुद्दे पर कानून अच्छी तरह से तय है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें निचली अदालत ने अभी तक आरोप तय नहीं किए थे। आरोप पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया गया था। कानून का तय प्रस्ताव यह है कि आरोपों पर सुनवाई के चरण में,

एच.

469 ए.

470 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 6 एस. सी. आर.

अभियोजन पर विश्वास किया जाना चाहिए। यदि कोई अपराध नहीं बनता है तो केवल एक आरोपी को आरोपमुक्त किया जा सकता है। उत्पादित सामग्री की सच्चाई, पर्याप्तता और स्वीकार्यता केवल परीक्षण के चरण में ही की जा सकती है। आरोप-पत्र के स्तर पर, न्यायालय को यह संतुष्ट करना होता है कि अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। उस स्तर पर न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता केवल तभी होती है जब यह अभिनिर्धारित करने के लिए मजबूत कारण हों कि यदि मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है, तो यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। [पैरा **11**] [473-डी-एफ]

बी.

2. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से अभियुक्त और प्रत्यर्थी नं. **1** के अन्य सहयोगियों के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग, पॉलीग्राफ परीक्षण और ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्रेचर प्रोफाइलिंग (बी. ई. ओ. एस.) परीक्षणों सहित मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का उल्लेख किए बिना पूरे साक्ष्य को दो पैरास में संक्षेपित किया था। **1** और प्रत्यर्थी **Nos.1** और **2** के निर्वहन का आदेश दिया। [पैरा **18**] [477-जी-एच; 478-ए]

सी.

डी.

3. हालांकि मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन परीक्षण रिपोर्ट केवल एक आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से सबूत का एक भौतिक टुकड़ा हो सकती है। रिकॉर्ड पर इस सामग्री के बावजूद, उच्च न्यायालय यह राय नहीं दे सकता था कि मामला आरोप तय करने के लिए भी नहीं बनाया गया था, जिसके लिए केवल प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना है। [पैरा **19**] [478-बी]

ई.

4. यदि मामले के तथ्यों की जांच इस विषय पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य को भी पूरी तरह से आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। बल्कि अनुसंधान के दौरान दर्ज किए गए कुछ व्यक्तियों के बयानों का चुनिंदा संदर्भ है। यह दर्शाता है कि मन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस तरह से अधिकार क्षेत्र का

प्रयोग किया था जो एक जघन्य अपराध के मुकदमे को रोकने के लिए निहित नहीं है।[पैरा **20**] [478-बी-डी]

एफ.

राजस्थान राज्य बनाम अशोक कुमार कश्यप **(2021) 11**

जी.

एस. सी. सी. **191**-पर निर्भर था।

महाराष्ट्र राज्य और अन्न. वि.डॉ. मारौती

एस/ओ।काशीनाथ पिंगलकर (2023) 4 एस. सी. सी. 298-संदर्भित।

एच.

471

कप्तान मंजीत सिंह विरदी (आर. ई. टी. डी.) बनाम हुसैन मोहम्मद शताफ एंड ऑर्स।

ए.

मामला कानून संदर्भ

(2023) 4 एससीसी 298

संदर्भित किया गया है

पैरा **4**

(2021) 11 एससीसी 191

उस पर भरोसा करें

पैरा **12**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2023 की आपराधिक अपील संख्या 1399।

बी.

2012 के सी. आर. एल. आर. ए. सं. 135 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

कुणाल चीमा, शिवम दुबे, राघव देशपांडे, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सी.

सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, हिमांशु भूषण, सुश्री आकृति प्रिया, कानू अग्रवाल, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, भरत बागला, सौरव सिंह, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

राजेश बिंदल, जे।

डी.

1. 2012 के संशोधन आवेदन संख्या 135 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17.07.2013 के आदेश को अपीलार्थी द्वारा चुनौती दी गई है।उपरोक्त आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अदालत द्वारा पारित दिनांक 21.02.2012 के आदेश को खारिज कर दिया है, जो प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदन संख्या।1 और 2 को आरोपमुक्त करने के लिए खारिज कर दिया गया।

ई.

2. विर्दी के बंगले, थोंबरेवाड़ी, लोनावाला के निवासी मनमोहन सिंह सुखदेव सिंह विर्दी की हत्या के लिए लोनावाला सिटी पुलिस स्टेशन में 14.05.2006 पर दर्ज 2006 की प्राथमिकी संख्या 46 से विवाद उत्पन्न होता है।उसका शव उसके कमरे में खून से लथपथ पाया गया।3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि एक लघु परीक्षण केवल अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए कुछ बयानों का उल्लेख करके किया गया है, जो आरोप पत्र का हिस्सा थे।आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर था।न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग, पॉलीग्राफ परीक्षण और ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्रेचर प्रोफाइलिंग (बी. ई. ओ. एस.) सहित मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन सहित मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन प्रत्यर्थी संख्या 1 और चार अन्य सहायकों पर किया गया था।

एफ.

जी.

एच.

472

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

ए.

प्रत्यर्थी नं.1, जो अपराध में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के आरोप की ओर ले जाता है।

4. दलीलों के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने राज्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा है।

महाराष्ट्र और ए. एन. आर. वी.डॉ. मारौती एस/ओ।काशीनाथ पिंपलकर 1.

बी.

5. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यह अंधी हत्या का मामला है, इसलिए कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। मृतक के साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 की कोई दुश्मनी नहीं थी। वे पड़ोस में खुशी-खुशी रह रहे थे। अभियोजन पक्ष द्वारा एक झूठी कहानी बनाई गई थी जिसका समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि निचली अदालत प्रत्यर्थी नं. 1 और 2। उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यदि उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ता है तो यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र की गई प्रासंगिक सामग्री पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया।

सी.

6. हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को राज्य द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने, जिसके पास इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है, यह तर्क देना चाहा कि विवादित आदेश को कानूनी रूप से कायम नहीं रखा जा सकता है क्योंकि आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में, साक्ष्य की सराहना संभव नहीं थी क्योंकि यह परीक्षण के बाद न्यायालय में साक्ष्य दर्ज होने के बाद ही हो सकता है। आरोप तय करने के चरण में केवल प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना है।

डी.

ई.

7. पक्षों की ओर से विद्वानों की विद्वान अधिवक्ता सुनी और अभिलेख और प्रासंगिक कागजातों का अध्ययन किया।

8. एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद, अनुसंधान की गई और Cr.P.C की धारा 161 और 164 के तहत कई व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। यहाँ तक कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग, पॉलीग्राफ परीक्षण और ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग (बी. ई. ओ. एस.) सहित मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन भी 31.5.2007 पर किया गया और इसी तरह के परीक्षण अन्य चार व्यक्तियों पर किए गए। बलिराम चिधू खाड़े, मोहन विजयम्मा श्रीधरन, अशोक गजराज चौधरी, महबूब दस्तगी शेख जो प्रत्यर्थी संख्या 1 के करीबी सहयोगी थे। 9. चूंकि यह एक अंधी हत्या थी, इसलिए अपराध की जांच की गई और हुसैन मोहम्मद के खिलाफ 09.12.2009 दिनांकित आरोप पत्र दायर किया गया।

एफ.

जी.

एच.

1 (2023) 4 एससीसी 298 ए

473

कप्तान मंजीत सिंह विरदी (आर. ई. टी. डी.) बनाम हुसैन मोहम्मद शताफ एंड ऑर्स। [राजेश बिंदल, जे।] ए.

शताफ और वहीदा हुसैन शताफ (प्रत्यर्थी एन. ओ. एस.)। 1 और 2) और ज़ानीश खान ने इसमें कहा कि जबकि प्रत्यर्थी नं।1 अपने व्यवसाय के उद्देश्य से दुबई में रह रहा था, उसकी पत्नी प्रत्यर्थी नं।2 मृतक के संपर्क में आया और दोस्ती विकसित की।वे अक्सर एक-दूसरे से मिलने लगे।दोस्ती शारीरिक संबंध में बदल गई।जब प्रत्यर्थी नंबर 1 दुबई से लौटा तो उसे इसके बारे में पता चला।बदला लेने के लिए, वह प्रत्यर्थी नहीं की मिलीभगत से।2 और एक ज़ानीश खान ने अज्ञात हमलावरों के माध्यम से मृतक को मारने की साजिश रची।

बी.

10. चूंकि मामला सत्रों द्वारा सुनवाई योग्य था, इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सत्र न्यायालय, पुणे को सौंप दिया गया था।इसके तुरंत बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने निर्वहन के लिए पुनरीक्षण आवेदन दायर किया।इसे निचली अदालत ने 21.02.2012 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था।उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के माध्यम से निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया था और प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को आरोपमुक्त कर दिया था।उपरोक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

सी.

डी.

11. अभियुक्त के आरोपमुक्त किए जाने के समय किस पर विचार किया जाना चाहिए, इस मुद्दे पर कानून अच्छी तरह से तय है।यह एक ऐसा मामला है जिसमें निचली अदालत ने अभी तक आरोप तय नहीं किए थे।आरोप पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया गया था।कानून का तय प्रस्ताव यह है कि आरोपों पर सुनवाई के चरण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पूरे साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए।यदि कोई अपराध नहीं बनता है तो केवल एक आरोपी को आरोपमुक्त किया जा सकता है।उत्पादित सामग्री की सच्चाई, पर्याप्तता और स्वीकार्यता केवल परीक्षण के चरण में ही की जा सकती है।आरोप-पत्र के स्तर पर, न्यायालय को यह संतुष्ट करना होता है कि अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम

दृष्टया मामला बनता है। उस स्तर पर न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता केवल तभी होती है जब यह अभिनिर्धारित करने के लिए मजबूत कारण हों कि यदि मुकदमे को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है, तो यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

ई.

एफ.

12. हाल के एक फैसले में इस मुद्दे पर कानून का सारांश दिया गया है।

राजस्थान राज्य बनाम अशोक कुमार कश्यप **2** में इस न्यायालय का प्रासंगिक

पैरास नीचे निकाले गए हैं:- “ 11.1.पी. विजयन बनाम केरल राज्य, (2010) 2 एस. सी. सी. 398 वाले मामले में, इस न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 पर विचार करने का अवसर मिला था कि आरोप तय करने और/या आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार करते समय किस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, उस पर विचार किया गया है।

जी.

2 (2021) 11 एससीसी 191

एच.

474

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

उक्त निर्णय में विस्तार से यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 227 के स्तर पर, न्यायाधीश को केवल यह पता लगाने के लिए साक्ष्य की छान-बीन करनी है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। यह देखा गया है कि दूसरे शब्दों में, आधारों की पर्याप्तता पुलिस द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य या अदालत के समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों की प्रकृति को अपने दायरे में ले लेगी जो प्रत्यक्ष रूप से खुलासा करते हैं कि आरोपी के खिलाफ संदिग्ध परिस्थितियां हैं ताकि उसके खिलाफ आरोप तय किया जा सके। यह भी कहा गया है कि यदि न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 228 के तहत आरोप तय करेगा, यदि नहीं, तो वह आरोपी को आरोपमुक्त कर देगा। यह आगे देखा गया है कि यह निर्धारित करने के लिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के लिए कोई मामला बनाया गया है या नहीं, मामले के तथ्यों के लिए अपने न्यायिक दिमाग का प्रयोग करते हुए, अदालत के लिए मामले के पक्ष और विपक्ष में प्रवेश करना या साक्ष्य और संभावनाओं का वजन और

संतुलन करना आवश्यक नहीं है, जो वास्तव में अदालत का कार्य है, मुकदमा शुरू होने के बाद।

बी.

सी.

डी.

11.2. कर्नाटक राज्य बनाम एम. आर. हीरेमथ, (2019) 7 एस. सी. सी. 515 में इस न्यायालय के हाल के निर्णय में, हममें से एक (डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.) ने पीठ की ओर से बोलते हुए पैरा 25 में कहा और कहा है:

“25. उच्च न्यायालय [एम. आर. हीरेमथ बनाम राज्य, 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 4970] को इस तथ्य का संज्ञान लेना चाहिए था कि निचली अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के प्रावधानों के तहत आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार कर रही थी। इस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले मापदंडों की अभिव्यक्ति इस न्यायालय के कई निर्णयों में पाई गई है। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि आरोपमुक्त करने के लिए एक आवेदन पर विचार करने के चरण में अदालत को इस धारणा पर आगे बढ़ना चाहिए कि अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में लाई गई सामग्री सही है और यह निर्धारित करने के लिए सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या सामग्री से उभरने वाले तथ्य, उसके अंकित मूल्य पर लिए गए हैं, अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक अवयवों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। राज्य में टी. एन. वी.एन. सुरेश राजन, (2014) 11 एस. सी. सी. 709, ने इस विषय पर पहले के फैसलों का समर्थन करते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

ई.

एफ.

जी.

‘29. ... इस स्तर पर, सामग्री के संभावित मूल्य पर गौर किया जाना चाहिए और अदालत से मामले में गहराई से जाने और यह मानने की उम्मीद नहीं की जाती है कि सामग्री दोषसिद्धि की गारंटी नहीं देगी।

एच.

475

कप्तान मंजीत सिंह विरदी (आर. ई. टी. डी.) बनाम हुसैन मोहम्मद शताफ एंड ऑर्स। [राजेश बिंदल, जे।] ए.

ए.

हमारी राय में, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या यह मानने के लिए कोई आधार है कि अपराध किया गया है और न कि क्या आरोपी को दोषी ठहराने के लिए कोई आधार बनाया गया है। इसे अलग तरह से रखने के लिए, यदि अदालत सोचती है कि आरोपी ने अपने संभावित मूल्य पर रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर अपराध किया होगा, तो वह आरोप तय कर सकता है; हालांकि दोषसिद्धि के लिए, अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि आरोपी ने अपराध किया है। कानून इस स्तर पर लघु परीक्षण की अनुमति नहीं देता है।”

बी.

13. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

सी.

“सुरेश थापा के दिनांक 11.12.2006 के बयान में, वह कहता है कि वह बंगले में पार्टी में शामिल हुआ था। 9.12.2007 पर दर्ज कलेक्टर सिंह ठाकुर के बयान में, उन्होंने आरोपी नं.2 13.5.2006 पर 7 बजे यहां तक कि यह बयान मुख्य रूप से आरोपी-याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए सक्रिय नहीं होगा क्योंकि उन्मूलन/हत्या की घटना देर रात हुई है। श्री सुरेश थापा ने 14.5.2006 पर अपने बयान में उल्लेख किया है कि देर रात वह घटनास्थल पर एक मंच पर बैठे थे, ऐसे समय में एक कार मृतक को छोड़ने आई और उसके बाद मृतक अपने माली हरि के साथ अपने घर चला गया। आई. डी. 1 पर दिए गए आगे के बयान में, उन्होंने समाज के क्षेत्र में आने वाली एक चांदी के रंग की टाटा इंडिया कार का उल्लेख किया और कार में से एक व्यक्ति ने मृतक को जोर से बुलाया, वह लंबा था और उसके लंबे बाल थे। मृतक आया और उक्त व्यक्ति के साथ बातचीत की जो बाद में मृतक के साथ बंगले में गया। 11.12.2006 के तीसरे बयान में, सुरेश थापा ने अपना पुराना बयान बदल दिया और कहा कि एक चांदी रंग की कार सोसाइटी के गेट पर आई और ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, मृतक अपने बंगले से बाहर आया, उसने दरवाजा खोला, मृतक ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर वह बंगला नं.5 और लौटते समय, कार उनके बंगले के पास खड़ी थी, चालक मृतक के पास आगे चला गया, हालांकि उनके बीच कोई संपर्क नहीं था। फिर वह आगे बढ़ा और "कैप्टन कैप्टन" को बुलाया, उन्होंने बातचीत की। व्यक्ति मृतक के साथ था और कार में 2-3 व्यक्ति बैठे थे। रमेश ढाकोल के पूरक बयान-एक अन्य प्रतिभूति, दिनांक 1.1.2007 में, वह आरोपी नं.2 रात में लगभग 2 से 2:30 बजे वापस आई और वह अपने बंगले में चली गई। वे कहते हैं, उनका पहले का बयान था

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

476

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

गलत है। डॉ. अजीत सिंह ने अपने दिनांकित 31.12.2006 बयान में मृतक और मृतक के साथ आरोपी एन. ओ. एस. के घर जाने का उल्लेख किया है। 1 और 2 अप्रैल, 2006 में। उसने मृतक को देखा और आरोपी नं. 2 एक झूले पर जबकि आरोपी नं. 1 पास ही था। यह उन्होंने 13.5.2006 पर देखा। ज़ार्निश (मोहम्मद) की पत्नी साजिदा बेगम का बयान। असगर) अभियुक्त-आवेदकों को फंसाता नहीं है। मृतक के भाई श्री मंजीत सिंह ने एक संवाद का उल्लेख किया है जो उन्होंने आरोपी नं. 1 अतीत में, जिसमें अभियुक्त नं. 1 कथित तौर पर उसे बताया गया कि मृतक सब कुछ खरीदना चाहता है, अगर समय मिले तो वह अपनी पत्नी को भी खरीदेगा। यह संवाद टेलीफोन पर था।

बी.

सी.

14. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि आरोप पत्र के साथ दायर जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई कुछ सामग्री को अस्पष्ट तरीके से संदर्भित किया गया है। सुरेश शेरबहादुर थापा, कलेक्टर ठाकुर सिंह, रमेश ढाकोल, मंजीत सिंह, डॉ. अजीत सिंह और साजिदा बेगम के बयानों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उनके बयानों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया है या किसी विशेष दिन पर दर्ज किए गए बयानों के केवल कुछ हिस्से पर ध्यान दिया गया है और इससे पहले या बाद में दर्ज किए गए बयानों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा, जांच एजेंसी ने हीरामन द्यानेश्वर चौधरी, रमेश मुरलीधर, मोहन बनाम, अशोक गुनाजी थोसर, महबूब दस्तगी शेख और रक्मा शिवराम वाघमारे के बयान दर्ज किए थे, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 को आरोपमुक्त करते समय संदर्भित और विचार नहीं किया गया है। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि यह अंधी हत्या का मामला था। परिस्थितियाँ केवल जाँच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री के माध्यम से ही अभियुक्त को दोषी ठहरा सकती थीं।

डी.

ई.

एफ.

15. मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग, पॉलीग्राफ परीक्षण और प्रत्यर्थी संख्या 1 के बी. ई. ओ. एस. सहित मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया। इसके अलावा अन्य चार व्यक्तियों का भी परीक्षण किया गया जो प्रत्यर्थी नं. 1, अहोक गजराज चौधरी, महबूब दस्तगीर शेख, बलिराम चिधू खाड़े और मोहन विजयम्मा श्रीधरन।

जी.

16. प्रत्यर्थी संख्या 1 पर किए गए परीक्षण की रिपोर्ट में, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय, गृह विभाग, महाराष्ट्र द्वारा प्रस्तुत राय, कैप्टन मनमोहन सिंह की हत्या में प्रत्यर्थी संख्या 1 की संलिप्तता को दर्शाती है। उनका मनोवैज्ञानिक ए

एच.

477

कप्तान मंजीत सिंह विरदी (आर. ई. टी. डी.) बनाम हुसैन मोहम्मद शताफ एंड ऑर्स। [राजेश बिंदल, जे।] ए.

प्रोफाइलिंग ने उनके सामाजिक मानदंडों के खिलाफ जाने की प्रवृत्ति के साथ एक असामाजिक व्यक्तित्व होने की ओर भी इशारा किया। रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:-

“मोहम्मद शताफ विषय का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन स्पष्ट रूप से कैप्टन की हत्या में उनकी संलिप्तता का संकेत देता है। मनमोहन सिंह ने पॉलीग्राफ के प्रश्नों पर धोखे और बी. ई. ओ. एस. पर महत्वपूर्ण जांच पर मौजूद अनुभवात्मक ज्ञान द्वारा संकेत दिया। इस निष्कर्ष की पुष्टि इस निष्कर्ष से हुई कि इस विषय में असामाजिक व्यक्तित्व के लक्षण हैं और सामाजिक रूप से वांछनीय तरीके से खुद को चित्रित करने की प्रवृत्ति है। नार्कोएनालिसिस इस विषय पर नहीं किया जा सका कि उन्होंने प्रक्रिया के लिए लिखित सहमति देने से इनकार कर दिया।

बी.

सी.

(जोर दिया गया)

17. इसके अलावा, चार अन्य व्यक्तियों के बारे में राय से पता चलता है कि मृतक की हत्या की जानकारी के बारे में सवाल का जवाब देने में छल था। रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:-

डी.

“अशोक गजराज चौधरी और महबूब दस्तगी शेख विषयों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन में कैप्टन की हत्या के मामले में मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग और पॉलीग्राफ परीक्षा शामिल थी। मनमोहन सिंह। अशोक गजराज चौधरी के संबंध में, भले ही उन्होंने हत्या के बारे में कोई जानकारी होने से इनकार किया, फिर भी उनकी पॉलीग्राफ जांच में हत्या के बारे में पता चला, फिर भी उनकी पॉलीग्राफ जांच से पता चला कि कैप्टन की मृत्यु से संबंधित जानकारी छिपाने से संबंधित प्रश्नों पर धोखा देने के उनके प्रयास थे। सिंह को किसी ने इस हत्या के बारे में जानकारी छिपाने के लिए कहा है, और वह जानता है कि पीड़ित को किसने मारा है। महबूब दस्तगी शेख के संबंध में, भले ही उन्होंने कैप्टन की हत्या में गवाह होने या मदद करने से इनकार किया हो। मनमोहन सिंह, या उनके बारे में कोई जानकारी होने के बावजूद, उनकी पॉलीग्राफ परीक्षा से पता चलता है कि कैप्टन की हत्या किसने की है। मनमोहन सिंह ”।

ई.

एफ.

जी.

(जोर दिया गया)

18. उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश के माध्यम से अभियुक्तों के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग, पॉलीग्राफ परीक्षण और ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग (बी. ई. ओ. एस.) परीक्षणों सहित मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का उल्लेख किए बिना पूरे साक्ष्य को दो पैरास में जोड़ दिया था।

एच.

478

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 6 एस सी आर।

और प्रत्यर्थी के अन्य सहायक नं।1 और प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 के निर्वहन का आदेश दिया।

19. हालांकि मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन परीक्षण रिपोर्ट केवल एक आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है, लेकिन निश्चित रूप से सबूत का एक भौतिक टुकड़ा हो सकती है। रिकॉर्ड पर इस सामग्री के बावजूद, उच्च न्यायालय यह राय नहीं दे सकता था कि मामला आरोप तय करने के लिए भी नहीं बनाया गया था, जिसके लिए केवल प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना है।

बी.

20. यदि मामले के तथ्यों की जांच इस विषय पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में की जाती है, तो यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य को भी पूरी तरह से आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। बल्कि अनुसंधान के दौरान दर्ज किए गए कुछ व्यक्तियों के बयानों का चुनिंदा संदर्भ है। यह दर्शाता है कि मन का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस तरह से अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया था जो एक जघन्य अपराध के मुकदमे को रोकने के लिए निहित नहीं है।

सी.

21. ऊपर वर्णित कारणों से, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

डी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.